International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

नकदी रहित अर्थव्यवस्था

डॉ. प्रकाश सीरवी

सह आचार्य अर्थशास्त्र एस.पी.सी. राजकीय महाविद्यालय अजमेर (राजस्थान)

सारांश

वर्तमान में वैश्विक स्तर पर नकदी रहित लेनदेन की ओर रूझान बढ़ता ही जा रहा है। भारत में विमुद्रीकरण के बाद से ही कैशलेस यानी नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। भारत नकदी रहित अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होने वाला पहला राष्ट्र नहीं है, बल्कि वैश्विक रूझान के कारण सभी देश कागजी मुद्रा के उपयोग को कम करने व डिजिटल माध्यमों के द्वारा नकदी रहित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लोगों के बीच इलेक्ट्रोनिक मनी उपकरणों का प्रसार करके वित्तीय ढांचा विकसित करके डिजीटल लेनदेन के प्रति लोगों को जागरूक करके प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में जनधन योजना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बैंक से जोड़ा जा रहा है जिससे एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जो नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे। नकदी रहित अर्थव्यवस्था वर्तमान व भविष्य की मांग भी है।

संकेत शब्द :– नकदी रहित, विमुद्रीकरण, तत्काल भुगतान सेवा, नेट बैंकिंग, ई भुगतान।

प्रस्तावना :–

वर्तमान समय नवाचारों से सम्बन्धित है। विश्व में सभी देश नई–नई तकनीक को अपनाकर अपने देश के विकास के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। वर्तमान में विश्व स्तर पर नकदी रहित लेन देन का रूझान बढ़ रहा है। अधिकतर लेन देन डिजिटल माध्यमों के द्वारा किया जाने लगा है। अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह ना के बराबर हो जाए तथा सभी लेनदेन डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा, राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक फंड्स ट्रांसफर और रीयल टाइम ग्रास सेटलमेंट जैसे इलेक्ट्रोनिक चैनलों एवं एकीकृत भुगतान इंटरफेस जैसे भुगतान माध्यमों से होने लगे तो यह स्थिति नकदी रहित अर्थव्यवस्था की होती है।

नकद रहित लेन देन का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इससे सभी लेनदेन पर नजर रहेगी, जिससे वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता आएगी, कालाधन कम होगा, भ्रष्ट्राचार में कमी आएगी, आतंकी संगठन व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में कमी आएगी, राजस्व बढ़ेगा, सार्वजनिक व्यय में बढ़ोतरी होगी जिससे भारत का विकास होगा। इस प्रकार नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लाभ और नवीन टेक्नोलॉजी से हो रही प्रगति को देखते हुए भारत भी तेजी से नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा है।

साहित्य समीक्षा

साहू जी पी, सिंह कुमार नवीन (2017) ने अपने लेख में भारत के डिजिटल भुगतान प्रणाली के सफल क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन करने का एक प्रयास किया है। इन्होंने अपने अध्ययन में सॉफ्टवेयर की मदद से नकदी भुगतान के 13 सफलता कारकों की पहचान की है जैसे– डिजिटल भुगतान के सफल क्रियान्वयन के लिए गुमनामी, बैंक की भागीदारी, दशज, बुनियादी ढांचा, गतिशीलता, पर्टियां, लोकप्रियता, भुगतान की सीमा, जोखिम, सुरक्षा, स्थानान्तरण सीमा, स्थानान्तरण मोड और स्थानान्तरण समय। इन्होंने अपना अध्ययन इलाहाबाद शहर पर किया है।

कोटकोव्स्की रैडोस्लाव व पोलासिक माइकल (2021) ने अपने लेख में कोविड 19 महामारी के दौरान भुगतान व्यवहार कैशलेस भुगतान की ओर स्थानान्तरित हो गया के बारे में बताया और यह बताया कि ऐसा लगता है कि महामारी के दौरान नकदी और नकदी रहित उपयोगकर्ताओं के बीच अन्तर बढ़ गया है। इन्होंने 22 यूरोपीय देशों के सर्वेक्षण के बाद बताया कि उपभोक्ता महामारी फैलने के पहले कैशलेस भुगतान कर रहे थे।

हसन असलम, अमान मोहम्मद आतिफ एवं अली मोहम्मद अशरफ (2020) ने अपने लेख "भारत में कैशलेस अर्थव्यवस्था : आगे की चुनौतियाँ" में बताया कि डिजिटल पैसे के साथ जीवन के साथ देश में एक नए युग का जन्म हुआ है। इन्होंने भारत में कैशलेस प्रणाली का प्रसार करने के लिए सरकार की योजनाओं एवं कैशलेस अर्थव्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों की चुनौतियों पर प्रकाश डाला है।

शोध पत्र का उद्देश्य :–

- भारत में नकदी रहित अर्थव्यवस्था के महत्व व उद्देश्यों से अवगत कराना।
- नकदी रहित अर्थव्यवस्था में डिजिटल साक्षरता के महत्व को बताना।

- भारत सरकार द्वारा नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रारम्भ की गई योजनाओं का अध्ययन करना।

शोध पत्र की विधि :–

यह शोध पत्र पूर्ण रूप से द्वितीय समंकों पर आधारित है। इसमें हमने विभिन्न पूर्व प्रकाशित शोध पत्र, पत्र–पत्रिकाएँ, भारत सरकार की वेबसाईट आदि को माध्यम बनाकर अपना शोध पत्र तैयार किया है।

शोध का महत्व :–

इस पत्र द्वारा हम नकदी रहित अर्थव्यवस्था के भारतीय अर्थव्यवस्था पर अल्पकालीन व दीर्धकालीन प्रभावों का अध्ययन करेंगे व यह बताने का प्रयास किया जाएगा कि नकदी रहित भुगतान से भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या लाभ होंगे। इस शोध पत्र द्वारा भारत में भारत सरकार द्वारा नकदी रहित लेनदेन को आकर्षित करने के लिए बनायी गयी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाएगा।

नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लाभ :–

- बैंकिंग सेवा प्रदान करने हेतु किसी स्थान विशेष पर पहुंचने की शर्त खत्म हो जाएगी, इससे ट्रांसपोर्ट खर्च में भी कमी आयेगी।
- कैशलेस लेनदेन बढेगा तो रिजर्व बैंक को कम नोट छापने होंगे, जिससे नोटों की छपाई पर आने वाली भारी लागत को कम किया जा सकता है।
- छोटी या बड़ी खरीदारी करने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक ही क्लिक पर वह उपलब्ध हो सकती है।
- डिजिटल ट्रांजेक्शन के माध्यम से अब धन का आदान प्रदान सुविधाजनक हो गया है।
- अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान में अब बिना एक्सचेंज रेट की चिंता किए सरलता से मुद्रा का आदान–प्रदान किया जा सकता है।
- डिजिटल खरीददारी पर छूट देकर नकदी रहित अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
- वित्तीय आंकड़ों का संग्रह आसान हो जाता है।
- कम जोखिम क्योंकि मोबाइल, कार्ड आदि गुम हो जाने पर उसे ब्लॉक करवाया जा सकता है।
- नकद चोरी से छुटकारा क्योंकि डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत हद तक सुरक्षित होते हैं।
- नकली मुद्रा का डर खत्म हो जाता है।
- मुद्राओं के माध्यम से फैलने वाली बिमारियों से राहत मिलती है।
- कुछ हद तक आपराधिक मामलों में कमी आती है।

नकदी रहित अर्थव्यवस्था से हानियाँ :–

- अधिक खर्च की संभावना बनी रहती है, लोग क्रेडिट कार्ड से अत्यधिक व अनावश्यक खरीददारी कर लेते हैं।
- वित्तीय व डिजिटल साक्षरता के अभाव में कैशलेस अर्थव्यवस्था प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकती है।
- भारत जैसे देश में अधिकतर लोग गांवों में रहते हैं जहाँ इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या मुश्किल से कनेक्टिविटी मिलती है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कैशलेस इकोनॉमी के लिए जो सुविधाएँ चाहिए जैसे बैंक, एटीएम मशीन इत्यादि वे आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं।
- स्मार्टफोन पर पूर्ण निर्भरता से लोग स्मार्टफोन खरीदने को मजबूर हो रहे हैं।
- भारत जैसे देश में काफी वित्तीय असमानताएँ हैं, जैसे अमीर व गरीब लोगों द्वारा कैशलेस पद्धति को स्वीकारने में बहुत अन्तर। गरीब डिजिटल साक्षर नहीं होते।
- भारत जैसे देश में कई बार लोग बुनियादी खर्चों के लिए नकद को डिजिटल करेंसी की तुलना में ज्यादा महत्व देते हैं।
- साइबर क्राइम की वजह से गोपनीयता का हनन होता है।
-

कैशलेस अर्थव्यवस्था के लिए सरकारी प्रयास :–

भारत सरकार ने नकदी रहित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए समय–समय पर कई पहल की है। सरकार द्वारा वित्तीय समावेशनों के लिए जनधन खातों को खोलना, आधार को कानूनी मान्यता देना, प्रत्यक्ष लाभ हस्तान्तरण का क्रियान्वयन, रूपे कार्ड जारी करना और अघोषित धन के लिए स्वैच्छिक प्रकटीकरण योजना के रूप में कई प्रयास किए हैं। इसके अलावा 1000 व 2000 रूपये की नोटबंदी इस दिशा में एक बड़ा कदम है। नोटबंदी के कारण डिजिटल भुगतानों में काफी तेजी आयी है।

- 3 लाख रूपये से अधिक का भुगतान नकद में नहीं किया जायेगा।
- सरकार ने विभिन्न छूटों के जरिये नकदी रहित भुगतान को बढ़ावा देने का प्रयास किया है जैसे कि पेट्रोल व डीजल की खरीद पर डिजिटल भुगतान करने पर उपभोक्ताओं को 0.75 बिक्री मूल्य के प्रतिशत की दर से छूट दी जाती है।
- ग्रामीण इलाकों में डिजिटल भुगतान के ढाँचे के विस्तार करने के लिए केन्द्र नाबार्ड के जरिये 10 हजार से कम आबादी वाले एक लाख गाँवों में प्रत्येक में दो POS लगाकर बैंकों को वित्तीय सहायता दे रहा है।
- डिजिटल माध्यमों से भुगतान करने पर रेलवे अपने उपनगरीय रेल नेटवर्क के जरिये मासिक या सीजनल टिकट के लिए ग्राहकों को 0.5 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करती है।
- सरकार क्रेडिट व डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड या अन्य पेमेंट कार्ड के जरिये भुगतान करने पर सेवा कर में छूट दे रही है।
- सरकार ने नकदी रहित भुगतान के इको सिस्टम में विस्तार के लिए, 10 लाख नए POS टर्मिनल जोड़ने की योजना बनायी है।
- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के साथ ही इसके लिए आवश्यकता और शिकायत निवारण तंत्रों को सुदृढ़ करने हेतु डाकघरों, उचित मूल्यों की दुकानों और बैंकिंग पत्र व्यवहार के माध्यम से ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

भारत में डिजिटल लेनदेन की संख्या बढ़ी है। 2019 (जून) में एकीकृत भुगतान इंटरफेस लेनदेन 754 मिलीयन रूपये तक पहुँच गया है। तुरन्त भुगतान सेवा और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम से होने वाला लेनदेन क्रमशः 171 मिलीयन और 26 मिलीयन रहा।

डिजिटल भुगतान के लिए बजट में किये गए प्रावधान :–

- जिन कारोबारियों का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रूपये या उससे अधिक है वे अगर डिजिटल पेमेंट के जरिये अपने ग्राहकों से भुगतान लेते हैं तो उनके पेमेंट पर कोई चार्ज या मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं देना होगा।
- 1 करोड़ रूपये से अधिक की नकदी निकासी पर 2 प्रतिशत TDS देना होगा।
- भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य बैंक उन लागतों पर निगरानी रखेंगे जिनके लिए कम नकदी का इस्तेमाल किया गया है ताकि लोग डिजिटल लेनदेन का अधिकतम इस्तेमाल कर सकें।
- इन प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आयकर अधिनियम और भुगतान व निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 में आवश्यक संशोधन किये जा रहे हैं।
- BHIM, UPI, UPI QR Code, Aadhar Pay, G.Pay, Phonepe, डेबिट कार्ड, NEFT और RTGS जैसे कई तरह के लो कॉस्ट डिजिटल पेमेंट मोड्स उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल नकदी रहित अर्थव्यवस्था के लिए किया जा सकता है।

निष्कर्ष :–

नकदी रहित अर्थव्यवस्था की अवधारणा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसप्रकार का लेनदेन व्यक्ति व सरकार दोनों के लिए लाभदायक है क्योंकि इससे व्यक्ति तक सरकार की पहुंच सम्भव हो पाती है जिससे वह जनकल्याण सम्बन्धित योजनाओं का सीधे लाभ उठा सकता है, साथ ही सरकार द्वारा नकदी रहित लेनदेन से कर वंचन में कमी आती है जो भ्रष्टाचार व आतंकवाद के वित्तपोषण को कम करता है। साथ ही कर वंचन से राजस्व में वृद्धि सरकार के आय के रूप में वृद्धि कर देती है जो सार्वजनिक व्यय परिलक्षित होगा व जनकल्याण को बढ़ावा देगा। नकदी रहित अर्थव्यवस्था एक ऐसा विचार है जिसको व्यवहारिक रूप से अपनाने का अब उचित समय आ गया है।

सन्दर्भ सूची :–

1ण साहू जी पी, सिंह कुमार नवीन (अक्टूबर–2017) डीओआई : 10.1007/978–3 –319–68557–1–40 सम्मेलन, ई बिजनेस, ई सेवाओं और ई सोसायटी पर सम्मेलन।

2ण कोटाकोव्स्की रैडास्लावएवं पोलासिक माइकल (दिसम्बर 2021) कोविड–19 महामारी ने यूरोप में नकद और केशलेस भुगतान उपयोगकर्ताओं के बीच विभाजन को बढ़ा दिया है। ELSEVIER, Economic Letters, Volume 209, दिसम्बर 2021, 110139

3ण हसन असलम, अमान मोहम्मद आतिफ एवं अली मोहम्मद अशरफ (2020) COMFINN Research, घर अभिलेखागार/खण्ड 8 नवम्बर 1 (2020) http://doi.org/10.34293/Commerce.8il.839

4ण भारत में कैशलेस लेनदेन : एक अध्ययन (रा) (ऑनलाइन) https://www.isdr.org/Papers/1)SDRI1902011.pdf इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक डेवलेपमेंट एण्ड रिसर्च।